कृषि अर्थशास्त्र और कृषि-व्यवसाय में कॅरिअर के अवसर

डॉ. रामचंद्र

भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित गतिविधियों पर निर्भर है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली लगभग 65 प्रतिशत आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है. इनमें से अधिकांश आबादी अपनी आमदनी का 90 प्रतिशत हिस्सा बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, ईंधन और स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च करती हैं. 50,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले 50 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवार इन आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं. इस प्रकार, भारत जैसे विकासशील देश में, आर्थिक विकास को ग्रामीण लोगों के बीच समृद्धि सुनिश्चित करनी चाहिए.

कोई संदेह नहीं है कि औद्योगिक उद्यमों और आधुनिक तकनीकों से शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न हो सकता है और कुलीन और अमीर निवेशकों को एक समृद्ध लाभांश का भुगतान किया जा सकता है. हालांकि, यह शहरी और ग्रामीण आबादी के साथ-साथ अमीरों और गरीबों के बीच की आर्थिक खाई को और चौड़ा कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप गरीबों को अधिक कठिनाई होगी. ग्रामीण विकास और कृषि उत्पादन में सुधार न केवल सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए बल्कि खाद्य आपूर्ति में आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है. हमारी जनसंख्या 1.35 बिलियन से अधिक होने की उम्मीद है, भोजन की वार्षिक मांग 2025 तक 195 मी. टन के वर्तमान स्तर से 250 मी. टन बढ़ने का अनुमान है क्योंकि खाद्य सुरक्षा आर्थिक प्रगति के लिए एक पूर्व आवश्यकता है इसलिए कृषि-आधारित विकास कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

हमारे राष्ट्रीय संसाधन

हालांकि खाद्य संकट एक गंभीर खतरा है, लेकिन इस संकट को एक व्यावसायिक अवसर में बदलने की अच्छी गुंजाइश है. वर्तमान में, हमारे अधिकांश प्राकृतिक संसाधनों की अत्यधिक उपेक्षा की जा रही है. 329 मिलियन हेक्टेयर के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से 175 मि. हेक्टेयर को बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है. यह बंजर भूमि न केवल बेकार पड़ी है, बल्कि हमारी कृषि और पर्यावरण-व्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रही है. हमारे जंगल तेजी से कम हो रहे हैं. वनों के तहत अनुशंसित 33 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में केवल 12 प्रतिशत क्षेत्र में पेड़ हैं. वनों की कटाई बेरोकटोक जारी है, क्योंकि 80 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों द्वारा खाना पकाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है और इसका लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा वनों और सामुदायिक भूमि से लिया जाता है. पहाड़ी इलाकों के ये बड़े हिस्से और उपेक्षित कृषि क्षेत्र जो वनस्पति से रहित हैं, पानी को सोख नहीं सकते. परिणामस्वरूप लगभग 75 प्रतिशत बारिश का पानी मैदान से बाहर चला

जाता है जिसके परिणामस्वरूप बाढ़, मिट्टी का क्षरण, जलाशयों की सिल्टिंग और नदी का जलस्तर कम हो होने जैसी समस्याएं होती हैं.

देश में 147 एम हेक्टेयर खेती योग्य भूमि में से केवल 44 एम हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो रही है और शेष क्षेत्र फसल उत्पादन के लिए अनियमित वर्षा पर निर्भर होते हैं. चूंकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि करना जोखिम भरा होता है, इसलिए किसान अपने फसल उत्पादन का अनुकूलन करने के लिए बाहरी आदानों में निवेश करने से हिचकिचाते हैं और इससे कम पैदावार होती है. यद्यपि पानी कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन अधिकांश किसान इसके विवेकपूर्ण उपयोग से अनभिज्ञ होते हैं और अपने खेतों में पानी भरते हैं. पानी के अत्यधिक उपयोग के परिणामस्वरूप, 9 एम हेक्टेयर से अधिक उपजाऊ भूमि खारी बंजर भूमि में बदल गई है. इस प्रकार कृषि अनुसंधान में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, भारत में खाद्य फसलों की औसत उपज चीन में 3 टन / हेक्टेयर और 4 टन / हेक्टेयर के विश्व औसत की तुलना में केवल 1.5 टन / हेक्टेयर है, किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करने के साथ-साथ उपयुक्त बीजों, पोषक तत्वों, पौधों की सुरक्षा, पोस्ट प्रोडक्शन और मार्केटिंग आउटलेट जैसे आवश्यक इनपुट्स और अवसंरचना में उचित तकनीकों और समय पर निवेश का चयन खाद्य उत्पादन को बढ़ा सकता है.

ग्रामीण लोगों को रोजगार और आय प्रदान करने की प्रबल क्षमता वाला पशुधन एक अन्य महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है. भारत में दुनिया का सबसे अधिक पशुधन है. 500 मिलियन में से, 204 मिलियन मवेशी हैं, जो वैश्विक कुल का लगभग 17 प्रतिशत है. 84 मिलियन भैंस हैं जो विश्व की 56 प्रतिशत पशु आबादी और लगभग 200 मिलियन भेड़ और बकरियां हैं. दुग्ध उत्पादन के लिए मवेशियों का विकास ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्थायी आर्थिक गतिविधि हो सकती है. मवेशियों को समाज के सभी वर्ग द्वारा अपनी जातियों और आय के स्तर के बावजूद पालते हैं और अगले 20 वर्षों के दौरान दूध और डेयरी उत्पादों की मांग में वृद्धि जारी रहेगी, जब तक कि वार्षिक उत्पादन 76 मि. टन से वर्तमान स्तर 150 मिलि. टन तक नहीं बढ़ जाता है. यह कार्य कठिन नहीं है, क्योंकि वर्तमान में इसका योगदान 5 मि. क्रॉसब्रेड गायों और लगभग 10 मि. भैंसों द्वारा किया जाता है, जो दुधारू पशुओं का केवल 15-20 प्रतिशत हैं. जबकि क्रॉसब्रेड गायों की औसतन दूध 6.5-7.0 किलोग्राम प्रति दिन और भैंस का 4.0 किलोग्राम / दिन होता है, शेष 85 प्रतिशत देशी गाय औसतन केवल 1 किलो प्रति दिन दूध देती हैं. भारत में मवेशियों की औसत दूध की पैदावार दुनिया के औसत 2380 किलोग्राम / दुग्ध की तुलना में केवल 987 किलोग्राम है. नस्ल सुधार, बेहतर चारे और स्वास्थ्य देखभाल के साथ, मौजूदा मवेशियों के उत्पादन में सुधार करना और उन्हें उच्च उपज वाले पशुधन में बदलना संभव है. मवेशी विकास एक अत्यंत आकर्षक व्यवसाय है, जिसमें केवल तीन क्रासब्रेड गायों के साथ, एक गरीब परिवार 15,000-18000 रुपये का वार्षिक लाभ कमा सकता है और अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकता है.

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बेकार पड़े सभी प्राकृतिक संसाधनों के साथ, इन परिसंपत्तियों के संरक्षक भी बेरोजगार हैं. चूंकि गैर-सिंचित क्षेत्रों में अकेले कृषि वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकती, इसलिए वर्ष के दौरान 6 से अधिक महीनों के लिए बड़े भूमि धारकों सहित अधिकांश किसान बेरोज़गार रहते हैं.

ऐसी स्थिति में, इन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयुक्त तकनीकों की शुरुआत की अच्छी गुंजाइश है जो स्थानीय समुदायों को स्थायी आजीविका प्रदान कर सकते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में विकास संबंधी समस्याएं बहुआयामी हैं। ृ कृषि उत्पादन और ग्रामीण समृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में संसाधनों, उपयुक्त प्रौद्योगिकियां की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, कुशल कर्मियों और किसानों में आत्मविश्वास की कमी होना है. गरीब होने के कारण, अधिकांश किसान समय पर महत्वपूर्ण निवेश प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं और इस तरह कम पैदावार होती है. सफल खेती के बाद भी, किसानों को अक्सर अधिशेष उत्पादन, भंडारण और विपणन सुविधाओं की कमी से उत्पन्न होने वाली विपणन समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इस प्रकार विकास कार्यक्रम को एक उद्यम के रूप में बढ़ावा दिया जाना चाहिए और किसानों को अपने खेतों को एक व्यवसाय के रूप में प्रबंधित करना चाहिए न कि परिवार की परंपरा के रूप में.

कृषि व्यापार

पायलट पैमाने पर कृषि-व्यवसाय संचालित करने के लिए प्रबंधन सिद्धांतों की प्रस्तुति ने हाल के दिनों में व्यापक लाभांश का भुगतान किया है. इस तरह के दृष्टिकोण के साथ, भारत दक्षिण देशों का नेतृत्व कर सकता है. उष्णकटिबंधीय मौसम की स्थिति सहित अत्यधिक श्रमिकों, भूमि और जल संसाधनों के साथ, भारत अन्य विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है और वैश्विक बाजार पर सत्ता स्थापित कर सकता है. बेहतर कृषि पद्धतियों और जल संसाधनों के प्रबंधन के साथ, भारत केवल 100 मि. हेक्टेयर की खेती करके और वाणिज्यिक महत्व की बढ़ती फसलों के लिए शेष 45 मि. हैक्टेयर आवंटित करके खाद्य पर्याप्तता प्राप्त कर सकता है. ये फसलें अच्छे निर्यात बाजार वाले फल, सब्जियां, फूल और औषधीय पौधे हो सकते हैं. अधिशेष भूमि का उपयोग मक्का और गन्ना जैसी फसलों की खेती के लिए भी किया जा सकता है और उत्पाद को आयातित पेट्रोलियम के विकल्प के रूप में शराब के औद्योगिक उत्पादन, अल्कोहल में परिवर्तित किया जा सकता है. इस तरह के औद्योगिक उत्पादों की अच्छी मांग होने के कारण उत्पादकों को सुनिश्चित बाजार और पारिश्रमिक मूल्य मिल सकता है. इस दिशा में हमारी कृषि का विस्तार करने की अच्छी गुंजाइश है.

प्रबंधन समर्थन

कृषि विकास कार्यक्रम को इसकी लाभप्रदता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रबंधन समर्थन की आवश्यकता है:

वित्त : भूमि विकास, सिंचाई प्रणाली और विपणन की व्यवस्था के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है. कृषि विकास के लिए वर्तमान वित्तीय संसाधन न तो पर्याप्त हैं और न ही समय-बद्ध. जल संसाधन विकास और भूमि को आकार देने जैसी कुछ गतिविधियों को हल्के ऋण की आवश्यकता होती है. इस उद्योग के विकास के लिए गांव स्तर के वितरण नेटवर्क के साथ अतिरिक्त वित्त की आवश्यकता है.

सूचना सेवा : नई फसलों, प्रौद्योगिकियों, प्रणालियों और उपज की मांग के बारे में जानकारी से मुनाफे को अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी. सूचना सेवाएं नई किस्मों, नई प्रौद्योगिकियों, कीट और रोग के प्रकोप और उनके नियंत्रण पर नवीनतम जानकारी एवं अनुभव भी प्रदान कर सकती हैं.

प्रौद्योगिकी अंतरण : चूंकि किसानों का एक बड़ा वर्ग प्रौद्योगिकियों और सूचना सेवाओं का प्रभावी उपयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं होता है, इसलिए पिछड़े किसानों को प्रेरित करने और शिक्षित करने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता होती है. यह कार्य कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा करने की प्रत्याशा की जाती है. इन क्षेत्र अधिकारियों को विभिन्न फसलों के लागत-लाभ विश्लेषण का अध्ययन करने और किसानों को उपयुक्त फसलों का चयन करने में मदद करने की आवश्यकता होती है. प्रौद्योगिकी के प्रभावी अंतरण के लिए, इन अधिकारियों और क्षेत्र के श्रमिकों को समय-समय पर उन्मुख होना चाहिए. लागत में कमी और बेहतर कीमत वसूली के माध्यम से मुनाफा बढ़ाने के लिए, मानव संसाधन विकास कृषि-व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए. यह छोटे किसानों में विश्वास निर्माण के साथ शुरु होना चाहिए.

विपणन सेवाएं : अपर्याप्त विपणन नेटवर्क कृषि में एक बड़ी अड़चन है. किसानों को विभिन्न वस्तुओं की मांग का तेजी से पूर्वानुमान लगाने और अवसरों का फायदा उठाने के लिए उन्मुख होना चाहिए. बहुत से बिचौलियों को शामिल किए बिना ग्राहकों तक पहुंचने के लिए बाजार आउटलेट स्थापित करने की अच्छी संभावनाएं है. व्यावसायिक घराने कच्चे माल की खरीद के लिए किसान संगठनों के साथ सीधा संबंध स्थापित कर सकते हैं. ऐसी एजेंसियां किसानों को उनकी फसल की उपज के अनुकूलन के लिए उन्नत किस्मों के बीज, वित्त और अन्य महत्वपूर्ण आदानों का समर्थन कर सकती हैं.

प्रबंधन कार्मिक : सफल कृषि व्यवसाय के लिए प्रबंधकीय कौशल वाला कार्य समर्पित कार्मिक होना एक महत्वपूर्ण इनपुट है. प्रबंधकों को क्षेत्र के स्थानीय कृषि कानूनों और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों से परिचित होना चाहिए. वास्तविक चुनौती छोटे किसानों को कुशल उत्पादकों के नेटवर्क में लाना है, ताकि सफलता में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके. इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत को नई प्रौद्योगिकियों और संसाधनों के साथ औद्योगिक विकास में भाग लेने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अवसर दिए हैं. हालांकि, हम कृषि की उपेक्षा नहीं कर सकते और ग्रामीण विकास के बिना आर्थिक प्रगति की उम्मीद करते हैं एग्री बिजनेस में अवसर बहुत अधिक हैं और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध तकनीकों से आसानी से लाभ प्राप्त किया जा सकता है. अब युवा प्रबंधकों के लिए आपसी लाभ के लिए इस चुनौती को स्वीकार करने का समय है.

भारत में कृषि शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालयों और कॉलेज के नाम:

- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, कृषि अर्थशास्त्र और व्यवसाय प्रबंधन विभाग.
- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, कृषि अर्थशास्त्र विभाग.
- चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, कृषि महाविद्यालय, कृषि अर्थशास्त्र विभाग.
- फाउंडेशन फॉर एग्रेरियन स्टडीज, बैंगलोर
- भारत सरकार, नई दिल्ली, राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र.
- गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, कृषि व्यवसाय प्रबंधन संस्थान.
- हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला, कृषि-आर्थिक अनुसंधान केंद्र.
- पूर्वी क्षेत्र भा.कृ.अ.प. अनुसंधान कॉम्प्लैक्स, पटना, सामाजिक-आर्थिक, विस्तार और प्रशिक्षण प्रभाग.
- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, कृषि अर्थशास्त्र प्रभाग.
- भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली.
- सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बैंगलोर, कृषि विकास और ग्रामीण परिवर्तन इकाई.
- ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आणंद.
- जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र.
- राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली.
- राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, डेयरी अर्थशास्त्र, सांख्यिकी और प्रबंधन प्रभाग.
- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद.
- सैम हिगिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय, (पूर्व इलाहाबाद कृषि संस्थान), कृषि अर्थशास्त्र और कृषि - व्यवसाय प्रबंधन विभाग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश.
- तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबटूर, कृषि अर्थशास्त्र विभाग.
- कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर, कृषि अर्थशास्त्र विभाग.
- कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर, कृषि विपणन और सहकारिता विभाग.
- दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान केंद्र.
- मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नै, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र विभाग.

(लेखक कृषि अर्थशास्त्र विभाग, सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एंव विज्ञान विश्वविद्यालय (पूर्व इलाहाबाद कृषि संस्थान) इलाहाबाद में सहायक प्रोफेसर है.) ईमेल : ramchandra@shiats. edu.in.

व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं.

(चित्र सौजन्य से: गूगल)